सी०सी०एल० के श्रमिकों की जबरन सेवा-निवृत्ति

3668. **श्री राम नरेश यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्री पुरुषोत्तम चमार, पम्प खलासी और छः अन्य श्रमिकों को सेंट्रल कोलफील्डस लि० के डिप्टी चीफ माइनिंग इंजीनियर, सौंदा, "डी" कोलियरी (हजारीबाग) द्वारा 28 जुलाई, 1986 को केवल 24 घंटे का नोटिस देकर गैर-कानूनी ढंग से सेवा से हटा दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई संसद सदस्यों ने अलग-अलग पत्र लिखकर माननीय ऊर्जा मंत्री से इन सात छंटनीग्रस्त श्रमिकों को बहाल करने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन श्रमिकों को बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं और वे कब तक बहाल कर दिये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सौंदा "डी" कोलियरी के श्री पुरुषोत्तम चमार, पम्प खलासी और 6 अन्य कर्मचारियों के मामले में यह पाया गया कि उनकी सेवा-पुस्तिका में जन्म तिथि या तो बिल्कुल ही दर्ज नहीं की गई थी या जानबूझकर उन्हें कम कर दिया गया था। अन्य प्रलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर उनकी सही जन्म-तिथि को निर्धारित करने में समय लग गया। जब तक उनकी सही जन्म-तिथि का पता चला, यह पाया गया कि ये कामगार अपने निवर्तन की उम्र से भी अधिक अवधि तक अपनी सेवा कर चुके थे। इसलिये इन्हें अल्प अवधि की सूचना के आधार पर अर्थात् दिनांक 28-7-88 से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊपर स्पष्ट की गई स्थितियों को देखते हुए उन्हें पुनः काम पर नियोजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Electricity bills of residents of trans Yamuna area

3669. SHRI CHATURANAN MISH RA; Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that electricity bills of the residents of trans-Yamuna area pertaining to several months are being sent together and the poor residents find it very difficult to pay the amount in lump sum;

(b) if so what are the details in thh regard and what are the reasons therefor; and

(c) whether Government will direct that authorities to issue atleast bimonthly bUls in this area?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) and (b) According to DESU, normally bills for two months consumption are sent at a time to domestic electricity consumers. However, issuing of bills got delayed in certain districts including Trans-Yamuna area mainly due to rapid increase in the number of consumer connections and large scale expansion of the transmission and distribution net work and the initial problems relating to computerisation of billing. To bridge the billing gap bills for 4-6 months are being sent by DESU to consumers including those in the Trans-Yamuna area. Consumers have the option to pay the bffls in instalments.

(c) According to DESU, once the billing gap is covered with the stabilisation of computerised billing, domestic consumers of DESU including those in the Trans-Yamuna area will get bi-monthly bills.